(d) and (e). The Government of Andhra Pradesh has not sought funds from the Government of India *specifically* for increasing Biodiversity in the forest lands. However, the Central Government has provided assistance to the Government of Andhra Pradesh for the following Afforestation Schemes:

Name of the Scheme	Assistance Provided (Rs. in lakhs)	
	(1992-93)	(1993-94)
1. Integrated Afforestation & Eco-Development Project . . .	45.00	389.87
2. Area Oriented Fuelwood & Fodder Project	..	40.00
3. Minor Forest Produce including Medicinal Plants	72.03	30.00

In the current year 1994-95 salso an allocation of Rupees 445 lakhs has been made for assistance to the Government of Andhra Pradesh for the above Schemes.

Cleaning of rivers under the National River Conservation Programme

2072. SHRI SARADA MOHANTY : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have recently identified some polluted rivers to clean them under the National River Conservation Programme:

(b) if so, the rivers identified for cleaning;

(c) whether any such polluted rivers in Orissa are also proposed for cleaning; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d). Yes, Sir| Based on survey conducted by Central Pollution Control Board and in consultation with the concered State Governments, the Government have identified River Godaveri in Andhra Pradesh; River Subarnrekha in Bihar; River Sabarmati in Gujarat; Rivers Tunga, Bhadra, Tungabhadra and Cauvery in KarnataMka; Rivers Betwa, Khan, Kshipra, Tapi, Chambal, Wain Ganga and mada in Madhya Pradesh; Rivers Krishna, and Godavari in Maharashtra; Rivers Mahanadi and Brahimini in Orissa; River Satluj in Punjab; River Chambal in Rajasthan and River Cauvery in Tamil Nadu; for taking up pollution abatement works in towns located on polluted stretches under the National River Action Plan. Studies are being carried out in respect of river Beas in Himachal Pradesh. River Kali in U.P. has been found to have pollution mainly caused by industrial effluents.

Killing of Animals in the Shimilipal Forest, Orissa

2073. SHRI SARDA MOHANTY : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the killing of elephants, tigers and other endangered species in Shimilipal forest in Orissa is on the increase;

(b) if so, the number of such incidents which have come to Government's notice during the last one year;

(c) the action initiated Government in this regard;

(d) the steps taken to stop the killings of such animals there; and

(e) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have reported poaching of nine elephants since January, 1994.

(c) to (e) The Cnief Widlife Warden has issued instruction to field officers to trengthen the intelligence network and also to intensify patrolling in the Similipal Tiger Reserve to check poaching activities.

ब्रिटेन में हिन्दू मंदिर को बन्द किया जाना

2074. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन के पू हर्त फोर्डशायर स्थित एक हिन्दू मंदिर को बन्द किया जा रहा है जिससे ब्रिटेन और भारत में रहने वाले हिन्दुओं में असंतोष और चिंता ब्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप कर संबद्ध अधिकारियों से इस समस्या का सौहादपूर्ण और संतोषजनक ढंग से समाधान करने के लिये अनुरोध करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (सलमान खूर्शीद): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर्तफोर्डशायर में हिन्दू मंदिर के रूप में भक्ति वेदांत मेनौर को सतत् कार्य करने देने के बारे में मंदिर प्रबंध मंडल तथा स्थानी हर्तस्मेर परिषद के बीच बातचीत चल रही है । यू०के० में भारतीय मूल के समुदाय के लोगों द्वारा व्यक्त चिंता को देखते हुये मंदिर को बन्द करने से संबद्ध प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया है और हर्तस्मेर परिषद इस विषय पर अक्तूबर, 1994 में और आगे बातचीत करेगी ।

(ख) वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में निर्णय यू०के० के कानूनी तथा राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाना है। लन्दन स्थित द्वारा हमारा हाई कमीशन संभव सीमा तक सभी संबंधियों से अनौपचारिक संपर्क बनाये हुये है और उम्मीद है कि इस मसले का कोई सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ लिया जायेगा ।

सौराष्ट्र में एक प्रथम क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोला जाना

2075. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, अहमदाबाद को सौराष्ट्र क्षेत्र से जिला-वार कितने आवेदकों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितने आवेदकों को पारपत्र जारी किये गये हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र के कितने आवेदकों के आवेदन-पत्र विचाराधीन है ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 तक सौराष्ट्र क्षेत्र से पारपत्रों के लिये जिला-वार कितने नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुये सौराष्ट्र क्षेत्र में एक पृथक पारपत्र कार्यालय खोलने का विचार रखती है ; और

(ड) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?